*वित्तीय प्रणाली को आघातसहनीय, भविष्य के लिए तैयार और संकट प्रतिरोधी रखना**

श्री शक्तिकान्त दास

प्रोफेसर शेरी मार्कोस[1]; डॉ. हिरोको ओउरा[2]; उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन; श्री अरिजीत बसु, अध्यक्ष, अकादमिक परिषद, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स; डॉ. रबी एन. मिश्रा, निदेशक, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स; विशिष्ट वक्ता और पैनलिस्ट; अकादमिक परिषद के सदस्य, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स; रिज़र्व बैंक के मेरे साथियों; देवियो और सज्जनो। नमस्कार।

मुझे भारतीय रिज़र्व बैंक के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (सीओएस) द्वारा आयोजित वित्तीय आघातसहनीयता पर वैश्विक सम्मेलन के दूसरे सत्र का उद्घाटन करने के लिए यहां उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है। सम्मेलन का पहला सत्र पिछले वर्ष अप्रैल में आयोजित किया गया था और मैंने उसमें भी भाग लिया था। वर्ष 2020 में अपनी स्थापना के बाद से, सीओएस ने न केवल रिज़र्व बैंक, बल्कि कुछ अन्य देशों के पर्यवेक्षकों की पर्यवेक्षी क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके जिन्होंने कॉलेज द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों[3] में भाग लिया है। संगठन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में उनके समर्पण के लिए टीम सीओएस को मेरी बधाई।

मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन में विश्व भर के प्रख्यात वक्ताओं,पैनलिस्टों और शिक्षाविदों ने भाग लिया है। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक वित्तीय समुदाय के हित के विभिन्न विषयों को कवर करेगा।

सम्मेलन का विषय, 'वित्तीय प्रणाली को आघातसहनीय, भविष्य के लिए तैयार और संकट-प्रतिरोधी रखना', वह है जो कभी भी प्रासंगिकता नहीं खोएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आर्थिक चक्र के किस पक्ष में हैं। वास्तव में, भविष्य के लिए तैयार होने और संकट के खिलाफ आघातसहनीय होने के लोकाचार को हर वित्तीय संस्थान में निर्मित करने की आवश्यकता है। यह उनकी संगठनात्मक संस्कृति का एक प्रमुख तत्व होना चाहिए। इसे सक्रिय रूप से तब विकसित किया जाना चाहिए जब प्रणाली प्रतिक्रियात्मक रूप से स्वस्थ हो, न कि प्रतिक्रियात्मक रूप से जब कार्यनीति बनाने और लागू करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश न हो।

सौभाग्य से, भारत में सभी हितधारकों, अर्थात्, रिज़र्व बैंक, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), और सरकार ने इस दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। भारत की घरेलू वित्तीय प्रणाली अब बहुत मजबूत स्थिति में है[4], जिसकी विशेषता मजबूत पूंजी पर्याप्तता, अनर्जक आस्तियों के निम्न स्तर और बैंकों और एनबीएफसी की स्वस्थ लाभप्रदता है। मैं ऐसे शानदार प्रदर्शन के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को बधाई देना चाहूंगा। हालांकि, संतोष के लिए कोई जगह नहीं है। हमें निरंतर निगरानी रखनी चाहिए और इस प्रगति को बनाए रखने के लिए सक्रिय उपाय करना जारी रखना चाहिए।

आज के परिवेश में, जो अशांत वैश्विक प्रभाव-विस्तार और अनिश्चितताओं की विशेषता है, वित्तीय क्षेत्र के लिए उभरती चुनौतियों के बीच अपना रास्ता बनाने के लिए एक अनुकूली और दूरंदेशी दृष्टिकोण का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह

* श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 20 जून 2024 - कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (सीओएस), आरबीआई, मुंबई द्वारा आयोजित वित्तीय आघात-सहनीयता पर दूसरे वैश्विक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण।

[1] डॉ. शेरी मरीना मार्कोस, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, एसेक्स विश्वविद्यालय, कोलचेस्टर, यूके और सीबीडीसी अकादमिक सलाहकार समूह, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूके एचएम ट्रेजरी।

[2] डॉ. हिरोको ओरा, प्रमुख, वित्तीय क्षेत्र आकलन और नीति प्रभाग, मिशन प्रमुख, एफएसएपी, भारत, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी, यूएसए।

[3] प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों के संयोजन के माध्यम से, कॉलेज पर्यवेक्षकों को अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और विधाओं से लैस करता है।

[4] अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) के लिए सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) का अनुपात मार्च 2024 (अनंतिम) के अंत में 2.74 प्रतिशत था, जो 31 मार्च 2023 को 3.87 प्रतिशत और 31 मार्च 2022 को 5.82 प्रतिशत से कम था। मार्च 2024 के अंत में 16.8 प्रतिशत पर जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी भी न्यूनतम नियामक आवश्यकता से बहुत अधिक है। एनबीएफसी का जीएनपीए अनुपात मार्च 2024 (अनंतिम) के अंत में 3.96 प्रतिशत था, जो मार्च 2023 के अंत में 5.03 प्रतिशत और मार्च 2022 के अंत में 6.29 प्रतिशत था। मार्च 2024 के अंत में 26.58 प्रतिशत पर जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी भी न्यूनतम नियामक आवश्यकता से काफी अधिक है।

अभिशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करने; स्थायी व्यापार मॉडल को रोजगार देने; और तकनीकी प्रगति को अपनाने और उन्हें हमारे लाभ के लिए उपयोग करने में सहायता करेगा। वित्तीय प्रणाली के दीर्घकालिक आघातसहनीयता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, जैसा भी आवश्यक हो, रिज़र्व बैंक अपनी ओर से विनियामक संरचना और पर्यवेक्षी कठोरता को ठीक करना जारी रखेगा। अब मैं इनमें से प्रत्येक पहलू पर विस्तार से बताता हूं।

अभिशासन

मजबूत अभिशासन आघातसहनीयता के मूल में है, खासकर वित्तीय क्षेत्र में। यह वास्तव में सूचित और कार्यनीतिक निर्णयों के लिए आधार है जो दीर्घकालिक लक्ष्यों और जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों के साथ संरेखित होते हैं। इस संदर्भ में, मैं तीन प्रमुख अनिवार्यताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले, प्रभावी अभिशासन निदेशक मंडल और कार्यकारी प्रबंधन के लिए स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्थापित करने पर जोर देता है। दोनों के पास सही निर्णय लेने और परिचालन पर प्रभावी ढंग से उचित निगरानी रखने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और स्वतंत्रता होनी चाहिए।

दूसरा, मजबूत अभिशासन में व्यापक आंतरिक नियंत्रण और मजबूत आश्वासन कार्यों को लागू करना भी शामिल है, अर्थात्, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन। आंतरिक नियंत्रणों को महत्वपूर्ण मुद्दों में बढ़ने से पहले संभावित जोखिमों का पता लगाने और कम करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। नियमित आंतरिक और बाहरी लेखांकन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे संगठन के वित्तीय स्वास्थ्य का स्वतंत्र आकलन प्रदान करते हैं। वे विनियामक आवश्यकताओं के वास्तविक अनुपालन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। नियमों का लापरवाही से पालन करना वास्तव में आत्म-पराजय होगा। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि प्रणालीगत स्तर पर, हमारी वित्तीय प्रणाली में अनुपालन संस्कृति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। रिज़र्व बैंक जहां कहीं भी कमियां पाता है, बाहरी संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय रूप से जाँचता है। जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन कार्यों के प्रमुख एक वित्तीय संस्थान के विवेक के रखवाले हैं। उनके पास संगठन के भीतर आवश्यक वरिष्ठता और स्वतंत्रता होनी चाहिए। बैंक या एनबीएफसी में ऐसे वरिष्ठ अपने संगठनों में अंतराल और कमजोरियों, यदि कोई हों, की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जोखिमों का प्रबंधन करने और संस्थान और इसकी प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने में मदद करते हैं।

तीसरा बिंदु जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं वह शासन में नैतिकता का महत्व है जिसमें कानूनों और विनियमों का अक्षरशः और मूल भाव से अनुपालन शामिल है; स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं का अनुसरण; और बिना सोचे समझे कोई सीमा निर्धारित करने से बचना।

व्यापार मॉडल

अब मैं बिजनेस मॉडल की ओर मुड़ता हूं। विनियमित संस्थाओं और पर्यवेक्षकों दोनों को संगठनों के व्यापार मॉडल में जोखिमों, यदि कोई हो, के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। जबकि व्यवसाय मॉडल को लाभप्रदता और वृद्धि के वाहक के रूप में डिज़ाइन किया जा सकता है, उनमें कभी-कभी कमियाँ होती हैं जो स्पष्ट नहीं हो सकती हैं। व्यवसाय को वृद्धि की ओर अग्रसर होना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अस्वीकार्य जोखिम लेने की कीमत पर कभी नहीं आना चाहिए। एक विनियमित इकाई के साथ-साथ समग्र वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक सफलता और आघात-सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत जोखिम शमन आवश्यक है।

जोखिमों का प्रबंधन करते हुए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

जैसे-जैसे वित्तीय क्षेत्र तेजी से डिजिटल हो रहा है, उन्नत तकनीकों को अपनाने से बैंकों और एनबीएफसी की विभिन्न जोखिमों का सामना करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता काफी मजबूत हो सकती है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये प्रौद्योगिकियां सुरक्षित, विश्वसनीय और संस्थान के समग्र कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हों।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत और उभरती प्रौद्योगिकियों

को संगठनात्मक कार्यों में एकीकृत करना वित्तीय संस्थानों के संचालन के तरीके को बदल सकता है। एआई और एमएल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बढ़ा सकते हैं और बैंकों और एनबीएफसी को संभावित जोखिमों और रुझानों की अधिक सटीक पहचान करने में सक्षम बना सकते हैं। ये प्रौद्योगिकियां वास्तविक समय में असामान्य पैटर्न और लेनदेन को पहचानकर धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार ला सकती हैं।

इस प्रकार, वे संस्थानों और उनके ग्राहकों को वित्तीय अपराधों और धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। नियमित कार्यों के स्वचालन के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार किया जा सकता है, जो मानवीय त्रुटि को कम करता है और अधिक कार्यनीतिक गतिविधियों के लिए संसाधनों को मुक्त करता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) मनुष्यों की तुलना में अधिक तेज़ी से और सटीक रूप से डेटा प्रविष्टि और लेनदेन प्रसंस्करण जैसे उच्च-मात्रा और दोहराव वाले कार्यों को संभाल सकता है।

चूंकि वित्तीय संस्थान अपने परिचालन को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों पर भरोसा करते हैं, इसलिए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता बढ़ सकती है। मज़बूती से सेवाएं देने में एक विक्रेता की असमर्थता सीधे विनियमित इकाई के परिचालन और ग्राहक सेवा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, तीसरे पक्ष के विक्रेताओं का चयन करने से पहले पूरी तरह से उचित परिश्रम आवश्यक हो जाता है। इसमें उनकी वित्तीय स्थिरता, तकनीकी क्षमताओं, सुरक्षा मानकों और विनियमों का पालन करने की उनकी क्षमता का आकलन करना शामिल है। इसके अलावा, तीसरे पक्ष के विक्रेताओं की निरंतर निगरानी होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सहमत मानकों और प्रथाओं का पालन करते हैं।

विनियामक ढांचे और पर्यवेक्षी कठोरता को उचित बनाना

जैसे-जैसे जोखिम विकसित होते हैं और नई चुनौतियां सामने आती हैं, रिज़र्व बैंक एक विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की रक्षा के लिए विनियामक ढांचे और पर्यवेक्षी प्रणालियों के संबंध में सतर्क, अनुकूली और सक्रिय रहने पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है।

पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने अपने द्वारा गठित विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 के तत्वावधान में विनियमों की व्यापक समीक्षा की है। कई निरर्थक निर्देशों को वापस लेने के अलावा, आरआरए ने अनुपालन को आसान बनाने और विनियामक बोझ को कम करने; रिपोर्टिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करने; और विनियामक निर्देशों में अधिक स्पष्टता लाने के लिए मूल्यवान सिफारिशें भी की हैं।

हाल के वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों (वाणिज्यिक और शहरी सहकारी बैंक दोनों), एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी), आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी), डिजिटल ऋणदाताओं, व्यष्टि-वित्त ऋणदाताओं और मूल-निवेश कंपनियों के लिए विनियामक संरचना का व्यापक पुनर्गठन किया है। इस प्रकार, वित्तीय क्षेत्र के विनियम अब न केवल बदलते समय के अनुरूप हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार और सक्रिय उपाय करने के लिए अपेक्षित तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। यह प्रणाली में हितधारकों के साथ अधिक परामर्श और घनिष्ठ इंटरफेस की सुविधा के लिए एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण है। यह नियमों को और भी गतिशील और सक्रिय बना देगा। साथ ही, मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि बार-बार विनियामक परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बदलती परिस्थितियों के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और जवाबदेही हो।

रिज़र्व बैंक ने अपनी पर्यवेक्षी प्रणालियों को भी काफी मजबूत किया है, एक इकाई-केंद्रित दृष्टिकोण से अधिक विषयगत और गतिविधि-आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गया है। अब हम बैंकों और एनबीएफसी के व्यापार मॉडल की धारणीयता को देखते हैं। समस्याओं और कमियों के मूल कारण का विश्लेषण किया जाता है। जहां भी हमें संकट दिखाई देता है या संकट महसूस होता है, अग्रिम कार्रवाई शुरू की जाती है।

[5] बैंकिंग पर्यवेक्षण, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण और सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण के पूर्ववर्ती विभागों को पर्यवेक्षण के एकल एकीकृत विभाग के रूप में विलय कर दिया गया।

वित्तीय क्षेत्र के समग्र मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक समूह के भीतर कई संस्थाओं की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए पर्यवेक्षण का एकीकृत विभाग[5] बनाकर रिज़र्व बैंक के भीतर संरचनात्मक परिवर्तन लागू किए गए हैं। ऐसा विचार पर्यवेक्षण की चपलता और व्यापकता को बढ़ाने के लिए है। अब अपरंपरागत तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। ऋण सूचना कंपनियों का ऑनसाइट पर्यवेक्षण वार्षिक और गहन बनाया गया है। जब किसी वित्तीय इकाई में समस्याएं बहुत गंभीर दिखाई देती हैं, तो कार्यपालक निदेशक के रैंक का रिज़र्व बैंक का एक वरिष्ठ अधिकारी संगठन के पूर्ण बोर्ड को संबोधित करता है और हमारी चिंताओं को साझा करता है। इसी प्रकार, जब हम लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और हमारे पर्यवेक्षी निष्कर्षों के बीच भौतिक विसंगतियां पाते हैं, या जब हम देखते हैं कि लेखा परीक्षकों द्वारा कुछ भौतिक मुद्दों को ठीक से संबोधित नहीं किया गया है, तो हम लेखा परीक्षकों को प्रत्यक्ष चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। ये पर्यवेक्षण के हमारे नए तरीकों के कुछ उदाहरण हैं।

कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र (सीओएस) अपने आप में हमारे पर्यवेक्षण की गुणवत्ता और हमारे पर्यवेक्षकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारी सक्रिय पहल का एक लाजवाब उदाहरण है। यह रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रणाली को मजबूत करने के हमारे प्रयासों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। सीओएस के जनादेश के मूल में पर्यवेक्षकों का पेशेवर विकास है, दोनों प्रारंभिक नींव स्तर पर और साथ ही उनके करियर में बाद के चरणों के दौरान भी। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षक गतिशील वित्तीय परिदृश्य में उभरती प्रवृत्तियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और पर्यवेक्षी और नियामक विकास से अवगत रहें।

अब जबकि रिज़र्व बैंक अपने शताब्दी वर्ष (आरबीआई @100) की ओर बढ़ रहा है, हमने ऐसी कार्यनीतियाँ तैयार की हैं जो इसे भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की तैयारी के लिए तैयार करेंगी। हम रिज़र्व बैंक को दक्षिणी विश्व[6] के एक मॉडल केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक नीतिगत कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं। हमारा लक्ष्य निरंतर क्षैतिज स्कैनिंग और समग्र जोखिम आकलन के साथ 'थ्रू द साइकिल' जोखिम मूल्यांकन ढांचे का निर्माण करके रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण को एक वैश्विक मॉडल बनाना है। इसमें अधिक ग्राहक केन्द्रित ढांचे की भी परिकल्पना की गई है जो पर्यवेक्षित संस्थाओं के आचरण में सुधार करके ग्राहकों के हितों की रक्षा और संवर्धन करे। इस लक्ष्य के अनुसरण में, हम सभी वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ियों से सक्रिय सहयोग की उम्मीद करते हैं जो मुझे यकीन है कि वे प्रदान करेंगे।

निष्कर्ष

अंत में, एक अधिक आघात-सहनीय, भविष्य के लिए तैयार और संकट प्रतिरोधी वित्तीय प्रणाली की ओर यात्रा जारी है। यह सभी हितधारकों से सामूहिक प्रयासों, नवाचार और अनुकूलन क्षमता की मांग करता है। मैंने कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया है जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अभिशासन और आश्वासन से लेकर टिकाऊ व्यापार मॉडल को अपनाने के साथ-साथ इसके जोखिमों का प्रबंधन करते हुए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। मैंने वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा में विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की भूमिका पर भी जोर दिया है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सभी हितधारकों के लिए इन सिद्धांतों और प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहना अनिवार्य है। मुझे विश्वास है कि वे भारतीय वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता और आघात-सहनीयता में योगदान देना जारी रखेंगे।

इसी के साथ, मैं इस तीन दिवसीय सम्मेलन के सफल विचार-विमर्श के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों की उनके प्रयासों के लिए सराहना करता हूं। मेरी कामना है कि अगले तीन दिन सार्थक आदान-प्रदान, नवान्वेषी विचारों और सहयोगात्मक समाधानों से भरे हों, जो हमारी वित्तीय प्रणाली को आघात-सहनीय, भविष्य के लिए तैयार और संकट प्रतिरोधी बनाए रखने की प्रक्रिया में योगदान देंगे।

[6] गवर्नर के मौद्रिक नीति वक्तव्य दिनांक 7 जून, 2024 का पैराग्राफ 2 देखें (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=58049)